



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102023-249159
CG-DL-E-05102023-249159

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 2023/आश्विन 11, 1945

No. 255]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: एडी (ओआई) - 25/2023

विषय: थाईलैंड और वियतनाम में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले "वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील पाइप और ट्यूब" के आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/28/2023-डीजीटीआर.—स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब मैनुफैक्चरर एसोसिएशन (दिल्ली) और स्टेनलेस स्टील पाइप्स ट्यूब मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (गुजरात) (इसके बाद "आवेदकों" के रूप में संदर्भित) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अनुसार नामित प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से नामित प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। पाटित की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए नियम, 1995 समय-समय पर यथा संशोधित (इसके बाद इसे "एडी नियम" भी कहा जाता है), जिसमें थाईलैंड और वियतनाम (इसके बाद "विषय देशों" के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न या निर्यात किए गए "वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील पाइप और ट्यूब" (इसके बाद "विषय माल" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में संदर्भित) के आयात पर पाटन रोधी जांच शुरू करने की मांग करता है। यह आवेदन भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों के दो संघों द्वारा 29 जुलाई 2021 के व्यापार सूचना 09/2021 के संदर्भ में दायर किया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब' है।
3. विचाराधीन उत्पाद स्टेनलेस स्टील शीट, स्केल्प, काँइल या प्लेटों का उपयोग कर निर्मित है। कच्चे माल को आवश्यक आकार में बनाया जाता है और उपयुक्त वेल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से वेल्डेड किया जाता है।
4. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 73 के तहत वर्गीकृत किया गया है और आगे, उपशीर्षकों 7306 40 00, 7306 61 00 और 7306 69 00 के तहत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद को 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 29 19, 7306 29 19, 7306 306 90 के तहत एचएस कोड के तहत आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
5. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 24 में दर्शाए गए अनुसार प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

6. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित विषय वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और दोनों समान वस्तुएं हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं, और इसलिए नियमों के तहत इन्हें 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनों के लिए आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया चीन जन. गण. से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (दिल्ली) और स्टेनलेस-स्टील पाइप्स ट्यूब्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (गुजरात) द्वारा संबंधित संघों के सदस्यों की ओर से 29 जुलाई 2021 के ट्रेड नोटिस 09/2021 के संदर्भ में आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि घरेलू उद्योग खंडित है, तो घरेलू उद्योग की ओर से एक संघ द्वारा आवेदन दायर किया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसे घरेलू उत्पादक कुल पात्र घरेलू उत्पादन के बड़े अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं। आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि पीयूसी का निर्माण करने वाले घरेलू उद्योग प्रकृति में खंडित हैं, भारत में विषय वस्तुओं के 100 से अधिक उत्पादक हैं। आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि याचिका दायर करने वाले घरेलू उत्पादक विषय देशों में विषय वस्तुओं के निर्यातकों या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, ऐसे उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
8. प्राधिकरण प्रथम दृष्टया यह देखता है कि एसोसिएशन ने घरेलू उत्पादकों की ओर से कार्य किया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और आवेदकों द्वारा दायर आवेदन की जांच के बाद, प्राधिकरण प्रथम दृष्टया नोट करता है कि आवेदक नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' का गठन करते हैं और आवेदन नियम 6 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडोंको पूरा करता है।
9. यह भी नोट किया जाता है कि 29 जुलाई 2021 के व्यापार नोटिस संख्या 09/2021 के अनुसार, "क्षति मार्जिन निर्धारित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण आवेदक घरेलू उत्पादकों की विस्तृत जांच को सीमित संख्या में घरेलू उत्पादकों तक सीमित कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण जांच के दौरान चोट और चोट के मार्जिन को निर्धारित करने के उद्देश्य से घरेलू उत्पादकों के एक उपयुक्त नमूने पर विचार करेगा।

घ. संबद्ध देश

10. वर्तमान पाटन रोधी जांच के लिए विषय देश थाईलैंड और वियतनाम हैं।

ड जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच की अवधि और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि शामिल है।

च. थाईलैंड और वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदकों ने दावा किया है कि उनके पास संबंधित देशों में प्रचलित घरेलू बिक्री मूल्य के बारे में जानकारी तक पहुंच नहीं थी। चूंकि उत्पाद के लिए कोई समर्पित टैरिफ वर्गीकरण नहीं है इसलिए आवेदक विषय देशों में आयात की कीमत या संबंधित देशों से निर्यात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।
13. आरंभ करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने थाईलैंड और वियतनाम के लिए उत्पादन की लागत के आधार पर लाभ और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ उचित लाभ मार्जिन के साथ सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

छ. निर्यात कीमत

14. विषय देशों से विषय वस्तुओं का निर्यात मूल्य विषय वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है। शुद्ध निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल ढुलाई, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक कमीशन क्रेडिट लागत के कारण मूल्य समायोजन किए गए हैं।

ज. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्यों की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है जो प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि पाटन मार्जिन थाईलैंड और वियतनाम से आयातित विषय वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि थाईलैंड और वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद उक्त देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में डंप किया जा रहा है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

16. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण और सापेक्ष रूप से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आयात की मात्रा में वृद्धि की दर मांग में वृद्धि की दर से बहुत अधिक है। आवेदकों ने दावा किया है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहा है और दबा रहा है। इसने क्षमता उपयोग और वस्तुसूची के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, और जांच की अवधि में इसकी लाभप्रदता में गिरावट आई है। आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में प्रतिकारी शुल्क और पर्याप्त क्षमता लागू होने के बावजूद घरेलू उत्पादक थाईलैंड और वियतनाम से आयात के कारण मांग में पर्याप्त हिस्सा प्राप्त करने में असमर्थ थे। पाटन रोधी जांच शुरू करने को उचित ठहराने के लिए संबंधित देशों से पाटित किए गए आयातों से घरेलू उद्योग को सामग्री को नुकसान पहुंचने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं।

ञ. पाटन रोधी जांच की शुरुआत

17. प्राधिकरण आवेदकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता और पर्याप्तता के रूप में संतुष्ट है। आवेदकों द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर और संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय माल के पाटन के संबंध में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि तक पहुंचने के बाद विषय वस्तुओं की कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी नुकसान और इस तरह की क्षति और पाटित किए गए आयात के बीच कारण संबंध, और अधिनियम की धारा 9ए के साथ-साथ एडी नियमों के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकरण, इसके द्वारा, संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटन रोधी जांच शुरू करता है। जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ट. प्रक्रिया

18. वर्तमान जांच के लिए नियमों के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

19. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पत्तों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

20. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
21. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति दे सकता है।
22. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
23. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जाँच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ड. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
25. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।
26. जहां कोई इच्छुक पक्ष प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
28. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
29. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी, जो प्रकृति से, गोपनीय और / या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
30. इच्छुक पक्षों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त की गई हो (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उस जानकारी के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
31. गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है और नियम 1995 के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और

पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक बयान, और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

32. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 24 में दर्शाए गए दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
33. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना किया गया कोई अनुरोध या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीय दावे संबंधी किसी अनुरोध को पर्याप्त और पूरे कारणों के विवरण के बिना प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
34. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध नहीं आवश्यक है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
35. प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को संतुष्ट होने और स्वीकार करने पर प्राधिकारी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।
36. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

ण. असहयोग

37. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या बाद में अलग-अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि यह उचित लगता है।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2023

Case No. AD (OI) - 25/2023

Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes originating in or exported from Thailand and Vietnam.

F. No. 6/28/2023-DGTR.—Stainless Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association (Delhi) and Stainless Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association (Gujarat) (hereinafter referred to as the “applicants”) have filed an application on behalf of the domestic industry before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “AD Rules”), for the initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “welded stainless steel pipes and tubes” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as the “subject countries”). The application has been filed by two associations of the domestic producers of the PUC in India in terms of the Trade Notice 09/2021 dated 29th July 2021.

A. Product under consideration

2. The product under consideration in the present investigation is 'welded stainless steel pipes and tubes'.
3. The product under consideration is manufactured using stainless steel sheet, skelp, coil or plates. The raw material is formed into required shape and welded through suitable welding process.
4. The product under consideration is classified under Chapter 73 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and further, classified under ITC HS Codes 7306 40 00, 7306 61 00 and 7306 69 00. The product under consideration is also being imported under the ITC HS Codes under 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 50 00, 7306 90 11, 7306 90 19 and 7306 90 90. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.
5. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority in terms of paragraph 24 of this initiation notification.

B. Like article

6. The applicants have claimed that there are no known significant differences in the goods produced by the applicants and that exported from the subject countries. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The applicants have claimed that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the petitioning domestic producers are being treated as 'like article' to the subject goods originating in or exported from the subject countries.

C. Domestic industry and standing

7. The application has been filed by Stainless Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association (Delhi) and Stainless-Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association (Gujarat) on behalf of members of the respective associations in terms of Trade Notice 09/2021 dated 29th July 2021, which states that in case the domestic industry is fragmented, the application may be filed by an association on behalf of the domestic industry, provided that such domestic producers represent major proportion of total eligible domestic production. The applicants have submitted that the domestic industry manufacturing the PUC are fragmented in nature, with more than 100 producers of subject goods in India. The applicants have submitted that the petitioning domestic producers are not related to exporters of subject goods in subject countries or importers of product under consideration in India. Further, such producers have not imported the product under consideration during the period of investigation.
8. The Authority *prima facie* observes that the association has acted on behalf of domestic producers. In view of the above, and after examination of the application filed by the applicants, the Authority *prima facie* notes that the applicants constitute 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).
9. It is further noted that as per Trade Notice No. 09/2021 dated 29th July 2021, "[t]he Authority for the purpose of determining injury margin may limit detailed examination of applicant domestic producers to a limited number of domestic producers." In view of the same, the Authority will consider an appropriate sample of domestic producers for the purpose of determining the injury and injury margin during the course of the investigation.

D. Subject countries

10. The subject countries for the present anti-dumping investigation are Thailand and Vietnam.

E. Period of investigation

11. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The injury analysis period covers the period of investigation and the three preceding financial years 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation.

F. Normal value for Thailand and Vietnam

12. The applicants have claimed that they did not have access to information regarding the domestic selling price prevailing in the subject countries. Since there is no dedicated tariff classification for the product, the applicants could not rely upon price of imports into the subject countries or exports from the subject countries.

13. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value for Thailand and Vietnam based on cost of production with addition for profits and selling, general and administrative expenses along with a reasonable profit margin.

G. Export price

14. The Export price of the subject goods from the subject countries has been determined by considering CIF price of the subject goods. Price adjustments have been made on account of port expenses, inland freight, ocean freight, marine insurance, bank commission & credit cost to arrive at the net export price.

H. Dumping margin

15. The normal value and the export prices have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level with respect to the subject goods imported from Thailand and Vietnam. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from Thailand and Vietnam is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the said countries.

I. Injury and Causal link

16. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished *prima facie* evidence regarding injury suffered as a result of the alleged dumping, resulting in significant increase in imports in absolute and relative terms. The rate of increase in volume of imports is much higher than the rate of increase in demand. The applicants have claimed that the imports are undercutting and suppressing the prices of the domestic industry. This has adversely impacted the performance of the domestic industry in respect of capacity utilization and inventories, and there has been a decline in its profitability in the period of investigation. The applicants have claimed that despite imposition of countervailing duty and sufficient capacities in India, the domestic producers were unable to obtain a substantial share in demand due to imports from Thailand and Vietnam. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries justifying initiation of anti-dumping investigation.

J. Initiation of Anti-Dumping Investigation

17. The Authority is satisfied as to the accuracy and adequacy of the information provided by the applicants. On the basis of the duly substantiated application filed by the applicants, and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted therein, concerning the dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

K. Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

L. Submission of Information

19. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd11-dgtr@gov.in and ddl6-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
20. The known producers/exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
21. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

23. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

M. Time Limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
26. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

N. Submission of Information on Confidential Basis

27. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
28. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
29. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
31. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
32. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of paragraph 24 of this initiation notification.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is not satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

O. Non-Cooperation

37. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority